SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat); Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If I allow everything, then what I shall I do with those who have got permission? I have to adjourn the House now. You can speak in the evening.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Madam, I would like to associate myself with a single sentence only—that the Central Government may release sufficient funds for the Gujarat State to meet the scarcity needs.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is better.

Iddigation facilities in Dungarpur, Rajasthan

श्री कनकमल कटारा : (राजस्थान) : मैडम, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिले डूंगरपुर–बांसवाड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर 75 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं । उनके समग्र विकास हेतु माही परियोजना बांसवाड़ा नहर की प्रस्तावित है। यह 125 किलोमीटर होगी जो कि जगपुरा नहर से निकलेगी । यह नहर डूंगरपुर जिले के आसपुर, सागवाड़ा तथा सीमलवाड़ा तहसीलों से होकर गुजरती है । इससे करीबन 169 गांवों के लोगों को, कृषकों को लाभ मिलेगा । इससे लगभग 21 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी । 1987 में इस नहर की अनुमानित लागत 112 करोड़ रुपये थी । वर्तमान में 200 करोड़ रुपये होने की संभावना है। बजट के अभाव में इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में यह कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है। मैं पुरजोर शब्दों में यह मांग करता हूं कि इस आदिवासी क्षेत्र में वहां के लोगों के उत्थान के लिये, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये माही-सागवाड़ा नहर का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाय । यह नहर जो है वह उस क्षेत्र के लिये बहुत ही वरदान सिद्ध होगी । आज वहां पर स्थिति ऐसी है कि वहां पर हर आदिवासी भाई गरीब है जो मुंबई, गुजरात तथा अन्य जगहों में मजदूरी के लिये इधर-उधर घूमता फिरता है । वहां का जन-जीवन शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत निम्न है । इसलिये वहां पर इस नहर का काम शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाय । अगर ऐसा किया गया तो यह वहां के लोगों के लिये बहुत ही फायदेमंद होगा । इस क्षेत्र की यह प्रमुख मांग है, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देकर इस काम को प्रारंभ करें । धन्यवाद ।

श्री गोविन्द राम मिरि (मध्य प्रदेश) : मैं इससे अपने को संबद्ध करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाय ।

Demand for creating of Tamil Nadu Land Reforms Measure

SHRI S. MUTHUMANI (Tamil Nadu): Thank you, Madam, for giving this opportunity. I would like to raise an important matter regarding an obstacle created by the Centre in the Tamil Nadu Government's attempt to bring about land reforms in the State.

The Government of Tamil Nadu has proposed to bring in an amendment to the Tamil Nadu Urban (Ceiling and Regulation) Act, 1978, to make a specific provision in the said Act so as to provide that the excess vacant land held by any corporation that is exempted from the ceiling provisions of the Act, should not be transferred by way of sale, mortgage, gift, lease or otherwise without the previous permission of the Competent Authority. Since the subject of the draft Bill falls within the scope of entry 18 of the State List as also entries 6, 7 and 48 of the Concurrent list, the Tamil Nadu Government sent copies of the Tamil Nadu Urban Land (Ceiling and Regulation) Amendment Bill, 1992 on 22-9-92 to the Union Ministry of Home Affairs for the concurrence of the Government of India. After that, nine reminders have been sent. The last reminder was sent yesterday.

But, for unknown reasons, the Government of India is maintaining a stony silence. The provisions of the draft Bill are consistent with the provisions of the Constitution, including those relating to the Fundamental Rights. Yet; because ol